श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजघाट के कुछ कर्मचारियों की बिना किसी नोटिस के छंटनी कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कर्मचारी दस वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे है और अब ये एक माह से भी अधिक समय से कार्यालय के सामने धरना दिये हुए हैं।

(ग) यदि हां, तो उनकी छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). राजघाट समाधि समिति के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान बदल दिये गये हैं तथा उनके कार्य के घंटे उन्हीं के ग्रेड के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान कर दिये गये हैं। समाधि समिति के कर्मचारियों की आवश्यकता को पुनः आंका गया तथा 25 चौकीदारों एवं 7 मेहतरों में से 5 चौकीदारों तथा 2 मेहतरों को अधिक पाया गया। समिति ने सात अधिक कर्मचारियों को नोटिस के स्थान पर एक महीने का वेतन देकर छंटनी कर दिया। उनमें से केवल एक की सेवा दस वर्ष से अधिक थी। कर्मचारियों ने अपने वेतन लेने से इन्कार कर दिया तथा समाधि क्षेत्र में टैंट लगा दिये तथा वहां आवासित कर रहे हैं। छंटनी का निर्णय दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में राजघाट समाधि समिति ने किया जो कि एक संविधिक निकाय (स्टैचुटरी बौडी) है।

मिट्टी के तेल का तस्कर व्यापार

2619. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
श्री निहाल सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मई, 1967 को अथवा उसके आस पास 6 हजार लिटर मिट्टी का तेल पकड़ा गया, जब वह चोरी-छिपे राजधानी से बाहर ले जाया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा इसमें कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) उस कम्पनी का नाम क्या है जिससे मिट्टी का तेल लिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Orders with Public Sectors

2620. **Shri D. N. Patodia:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state the value and particulars of various orders for engineering goods placed by the various Government Departments on Public Sector Industries and on Private Sector Industries separately from 1961-62 until 1966-67 through the Directorate General, Supplies and Disposals?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): A statement showing the value of orders placed by the Directorate General of Supplies and Disposals for engineering and allied stores during the period 1962-63 to 1966-67 (upto February 1967) separately on supplier/manufacturers in